staffing and suggest measures for containing expenditure on staff within reasonable limits;

(d) Review the existing arrangements for planning execution, monitoring and evaluation of major projects and programmes and make suitable recommendations so that without detracting from accountability, the decision making process is expedited, cost escalations and delays are avoided and optimum benefit is derived from the expenditure incurred.

(e) Review present arrangements for sanctioning and controlilng expenditure and suggest how these arrangements can be improved to make financial control more effective and at the same time implementation of projects speedier; and

(f) Consider any other relevant matter and make suitable recommendations.

The Commission will be headed by Shri S. N. Mishra, Member, Lok Sabha. The names of other members of the Commission will be announced shortly after their consent has been obtained.

The Commission will be requested to make its reports in parts so that action can be taken as and when each part of the report is received, and to submit its final report within a year.

The Government hopes that as a result of comprehensive study by the Expenditure Commission, it would be possible to effect substantial economies in Government expenditure.

14.30 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) PROTECTION OF FORESTS TO CENTRAL FLOODS.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर): सभापति महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं :—

अब इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है कि बाढ़ों के वेग को तीव्र करने में नदियों के पर्वतीय जलागम क्षेत्रों में वनस्पतिक-कवच का ह्रास सहायक होता है । हमारी अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है और राष्ट्रीय वन-नीति के अनुसार वहां कम-से-कम 60 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिये । परन्तु पश्चिमी हिमालय में यह 38 और 45 प्रतिशत के बीच है । इस में भी हरियाली का क्षेत्र तो एक अनुमान केवल 14, 14 प्रतिशत ही है । नदियों के उद्गम वाले सीमान्त जिलों लद्दाख, लाहौल स्पिति, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में यह बहुत कम है । बाढ़-नियंत्रण और जल एवं मुद्रा संरक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध-स्तर पर पेड़ लगाये जायें, परन्तु जब तक यह पेड़ बड़े-बड़े न हो जाय, तब तक रहे-सहे यह पेड़, जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बचाये जायें ।

पर्वतीय वनों के विनाश का एक मुख्य कारण इनका व्यापारिक दोहन है । इसके खिलाफ और स्थानीय अर्थ-व्यवस्था का स्वावलम्बन बनाने के लिये पिछले वर्षों से उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड क्षेत्र में एक सशक्त जन-आन्दोलन चल रहा है जिस में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है । उन्होंने मौजूदा वन-प्रबन्धक के इस क्षेत्र की क्या स्थिति है, जंगल के उपकरण लीसा, लकड़ी और व्यापार के खिलाफ एक नया नारा बुलन्द किया है, वह है —

क्या हैं जंगल के उपकार ? मिट्टी पानी और बयार (आक्सीजन),

क्योंकि ये हैं जिन्दा रहने के आधार ।

इस में उन क्षेत्रों के लिये एक स्थायी और स्वावलम्बी अर्थ-व्यवस्था और सारे देश को बाढ़ों से मुक्ति दिलाने तथा नदियों के जल-प्रवाह को स्थिर रखकर सिंचाई और विद्युत उत्पादन के द्वारा समृद्धि की ओर ले जाने की योजना का बीज है ।

वनों की कमाई से तुरन्त आर्थिक लाभ उठाने वाली शक्तियां जिनमें राज्य सरकारें, ठेकेदार और वन निगम और छोटे-बड़े उद्योग शामिल हैं— संगठित होकर वन नीति में बुनियादी परिवर्तन के प्रश्न को टाल रही है और अल्प-जीवि अर्थ-व्यवस्था का एक लुभावना चित्र प्रकृति विज्ञान (इकालोजी) के आधार पर प्रस्तावित वन-प्रबन्ध की योजना के मुकाबले में खड़ा कर रही है, क्योंकि बाढ़, भूस्खलन और प्रकृति संरक्षण राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है । इसलिए भारत सरकार को इस दिशा में शीघ्र कदम उठाना चाहिये । इसके लिये यह आवश्यक है कि वन-प्रबन्ध, भूमि-संरक्षण, पर्यावरण, भूगर्भ-विज्ञान, वन्य-जन्तु

डा० रामजी सिंह

संरक्षण, वनस्पति विज्ञान आदि विभिन्न संबंधित क्षेत्रों के चोटी के वैज्ञानिकों की राय से यह निश्चित किया जाये कि बाढ़ और भूस्खलन को रोकने तथा जल व भू-संरक्षण को प्राथमिकता देकर पर्वतीय वनों के प्रबन्ध की नीति क्या हो ?

नई वन नीति बनने व उस पर अमल होने तक, स्थानीय न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापारिक वन-दोहन स्थगित रखा जाये। मृत, सूखे और गिरे पेड़-पेड़ों से काम चलाया जाये।

(ii) REPORTED SHORTAGE OF GUNNY BAGS CAUSING DIFFICULTY TO FARMERS AND TRADERSS

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : मैं 377 नियम के अधीन यह कहना चाहती हूं कि बोरों की कमी के कारण किसान व व्यापारियों को बड़ी भारी दिक्कत है। एक बोरी 9 रुपये की मिलती है, और नहीं भी मिलती है। हरयाणा सरकार को भी बोरियों की बड़ी भारी कमी है। अतः शीघ्र ही बोरियों की सप्लाई होनी चाहिये, नहीं तो लाखों मन अनाज खराब हो जायेगा। पता पड़ा है कि शार्टेज आर्टिफिशियल है।

(iii) REPORTED DECISION OF THE GOVERNMENT TO S@IFT THE BOEINGS OVERHAULING SITE FROM DUM DUM TO HYDERABAD.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): With your permission, I would like to raise the following matter under Rule 377.

The Project under the auspices of the Indian Airlines to overhaul the Boeings was to be set up at Dum Dum Airport areas. For this purpose, the Indian Airlines took a lease of 16 acres of land from the International Airport Authorities. The estimates cost of the Project is Rs. 20 crores. The Project shall initially provide employment to about 400 persons. The project shall be, it is understood further expanded and may employ more than 4000 persons after four years.

The Managing Director and Chairman of the Indian Airlines communicated to the Secretary of Indian Air Crafts Technicians Association, Mr. Gupta, in December last the decision of the Indian Airlines to set up the Project at Dum Dum Airport rea.

At present, Indian Airlines have a Fokker Friendship Engineering Base at Dum Dum. Fokker Friendship planes are gradually being phased out. The skill and talent of the engineers of this Institution have earned international repute and recognition.

Boeings are now being overhauled at Bombay in our country or in France, West Germany, Newzealand and Canada outside. The Indian Airlines have decided to develop indigenous capacity to undertake the repairings and overhauling works of the Boeing Engines of our country.

From all points of view, Dum Dum was considered to be the best location site for such a new project equipped with most modern and sophisticated equipments.

The Government of West Bengal undertook the responsibility of providing all infra-structural facilities including the supply of power despite the continuing crisis in power production in the State.

But it is reported, that the Government of India have recently decided to shift the location site from Dum Dum to Hyderabad.

Dum Dum being the international Airport, foreign countries might have chosen the Dum Dum workshop to get their Boeings overhauled and repaired.

The reported decision of the Government to change the location site, is really unfortunate and I would request the Government not to revise the earlier decision taken by the Indian Airlines in regard to the location of the proposed 20 crore-project in the interest of Indian Airlines in general and of West Bengal in particular.